केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत आवंटन योजनावार नहीं किया जाता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रस्तावों और उनके पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर धनराशि प्रदान की जाती है।

Decontrol of bulk drugs

994. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to decontrol some bulk drugs;

(b) if so, what are these bulk drugs proposed to be decontrolled;

(c) the reasons led to the decontrol of these drugs; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (d) Drugs have been kept under price control in accordance with the criteria laid down in 'Modification in Drug Policy, 1986'. However, certain representations have been received from time to time subsequent to announcement of DPCO, 1995 on 6.1.1995 regarding inclusion of certain bulk drugs. A Committee has been constituted to look into the matter.

Extension after superannuation given to higher officials in SAIL

995. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government have granted extension after superannuation to some of the high officials in SAIL;

(b) if so, the reasons and justification for granting such an extension;

(c) whether Government have imposed ban on extensions of higher officials in PSUs;

(d) if so, whether the orders of Government have been grossly violated by the SAIL; and

(e) if so, action Government propose to take to cancel the extension to higher ups in SAIL?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) The Government have extended the tenure of the present Chairman, SAIL, for a period of one year beyond the date of his superannuation, i.e. 30.11.95. The extension has been granted in the interest of the organisation for the sake of continuity especially when SAIL is emerging as a truly internationally recognised company.

(c) to (e) Steel Authority of India Limited has not granted extension after superannuation to any higher official in SAIL.

Export of Gram Dal

996. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to export the gram dal;

(b) whether the proposal has been cleared;

(c) if so, the total quantum of gram dal proposed to be exported; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) to (d) Yes, Sir. The quantity of 20,000 MTs of gram/gram dal has so far been approved for export during the year 1995-96. In addition, export of 34,000 MTs of gram/gram dal has also been agreed to by the Ministry of Agriculture. (out of the 34,000 MTs -- 14,000 MT are for NAFED and STC).

"ट्राइसेम" कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां

997. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में राजकोट के शहरी क्षेत्रों में "ट्राइसेम" कार्यक्रम की अब तक क्या उपलब्धियां रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी एजेन्सियों के बीच समन्वय के अभाव के कारण राजकोट के शहरी क्षेत्र में इस कार्यक्रम को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है;

(घ) क्या सरकार इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इसे राजकोट महानगर परिषद के माध्यम से कार्यान्वित करने का विचार रखती हैं; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) से (ङ.) "ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना" को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य मात्र ग्रामीण युवाओं को तकनीकी एवं उद्यमवृत्ति शिक्षा प्रदान करना है। जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में राजकोट के शहरी क्षेत्रों में ट्राइसेम कार्यक्रम की उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा गया है, तो अभी प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

Sale of equity of Visakhapatnam Steel Plant

998. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to sell equity of Visakhapatnam Steel Plant;

(b) whether it is a fact that adequate finance have to be located for expansion;

(c) quantum of funds required for expansion of Visakhapatnam Steel Plant;

(d) the manner in which Government propose to raise this needed funds; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) No, Sir.

(b) to (e) No decision has been taken so far on the expansion of Visakhapatnam Steel Plant.

मध्य प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए जिला पुनर्वास केन्द्र

999. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य में किन-किन जिलों का चयन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा आवंटित राशि का जिलावार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (घ) जिला पुनर्वास केन्द्र, विलासपुर जो पहले ही कार्य कर रहा है, के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में किसी जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्ष 1995-96 के लिए जिला पुनर्वास केन्द्र, विलासपुर के लिए बजट 14.36 लाख रूपए हैं।

पेयजल की आपूर्ति

1000. **श्री रामजीलाल:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां पर पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है तथा ऐसे कौन-कौन से राज्य है जहां पर यह उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) जिन राज्यों में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है वहां पर वाटर टैंक तथा इसकी आपूर्ति बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल): (क) 31.1.96 की स्थिति के अनुसार हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कवर न की गई बसावटें हैं।

(ख) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को जारी की जाने वाली निधियों के 10 प्रतिशत को जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन व रख-रखाव के लिए निर्धारित किया जाता है। इसे राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियों के 10 प्रतिशत द्वारा और अनुपूरित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Charge chrome plants in Orissa

1001. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the number of charge chrome plants in Orissa;

(b) whether some of these charge chrome plants have baen closed down;

(c) if so, the reasons for the closure of these charge chrome plants; and